

## MASTER OF ARTS (HISTORY) (MAHI)

Term-End Examination December, 2024

### "MARATHON CLASS"

MHI-107: HISTORY OF INDIAN ECONOMY-2 (C.1700-2000)

#### 1. What was the focus of the British Indian land policy?

ब्रिटिश भारतीय भूमि नीति का मुख्य ध्यान क्या था?

- **Revenue Extraction:** The British aimed to extract maximum revenue from the land. This was achieved through systems like the **Zamindari System**, **Ryotwari System**, and **Mahalwari System**, each targeting different ways of collecting taxes from peasants or landlords.

**राजस्व का अधिकतम संग्रहण:** ब्रिटिशों का उद्देश्य भूमि से अधिकतम राजस्व प्राप्त करना था। इसके लिए **जमींदारी प्रणाली**, **रियतवारी प्रणाली**, और **महलवारी प्रणाली** जैसी व्यवस्थाएं लागू की गईं, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य किसानों या जमींदारों से कर वसूलने का अलग तरीका था।

In the **Zamindari System**, introduced by Lord Cornwallis in 1793, the British made the landowners (zamindars) responsible for collecting taxes from peasants and remitting them to the British government. The zamindars often exploited the peasants, demanding higher taxes and leaving them in debt, which resulted in widespread poverty and social unrest.

**जमींदारी प्रणाली** में, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया, ब्रिटिशों ने भूमि मालिकों (जमींदारों) को किसानों से कर वसूलने और ब्रिटिश सरकार को जमा करने का जिम्मा सौंपा। जमींदार अक्सर किसानों से अधिक कर वसूलते थे और उन्हें कर्ज में डुबो देते थे, जिससे व्यापक गरीबी और सामाजिक अशांति फैली।

- **Land Ownership and Control:** The British sought to establish clear ownership of land, often giving zamindars (landlords) or other intermediaries control over the land, which led to the concentration of land in the hands of a few. This weakened the traditional system of village-based land ownership and control.

**भूमि स्वामित्व और नियंत्रण:** ब्रिटिशों ने भूमि का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके तहत जमींदारों (भूमि मालिकों) या अन्य मध्यस्थों को भूमि पर नियंत्रण दिया गया। इसके कारण पारंपरिक ग्रामीण भूमि स्वामित्व और नियंत्रण कमजोर हुआ।

In the **Permanent Settlement of Bengal** (1793), the British fixed the land revenue at a high rate, and zamindars were given the authority to collect taxes from peasants. This led to zamindars owning large tracts of land while peasants were left with very little control or rights over the land they worked on.

**बंगाल के स्थायी समझौते** (1793) में, ब्रिटिशों ने भूमि राजस्व को उच्च दर पर तय किया, और जमींदारों को किसानों से कर वसूलने का अधिकार दिया। इसके परिणामस्वरूप जमींदारों के पास बड़े-बड़े भूखंड थे, जबकि किसानों के पास उस भूमि पर नियंत्रण या अधिकार बहुत कम थे, जिस पर वे काम करते थे।

- **Commercialization of Agriculture:** The British encouraged the growth of cash crops like indigo, cotton, and opium, which were needed in global markets, sometimes at the expense of food crops. This was intended to benefit British industries and trade, though it often led to famines and hardships for local farmers.

**कृषि का व्यवसायीकरण:** ब्रिटिशों ने ऐसे नकद फसलों की खेती को बढ़ावा दिया, जैसे नील, कपास और अफीम, जो वैश्विक बाजारों में आवश्यक थे, हालांकि कभी-कभी यह खाद्य फसलों की खेती को नुकसान पहुँचाता था। यह ब्रिटिश उद्योगों और व्यापार को लाभ पहुंचाने के लिए था, लेकिन इससे स्थानीय किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

The British encouraged the cultivation of cash crops like **indigo, cotton, and opium**. In Bengal, farmers were forced to grow indigo for export, instead of food crops, leading to food shortages and famines. One of the most famous examples is the **Indigo Revolt** of 1859-1860, where farmers rebelled against the forced cultivation of indigo.

ब्रिटिशों ने नकद फसलों जैसे **नील, कपास** और **अफीम** की खेती को बढ़ावा दिया। बंगाल में किसानों को खाद्य फसलों की जगह नील उगाने के लिए मजबूर किया गया, जिससे खाद्य संकट और अकाल पैदा हुआ। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण **नील विद्रोह** (1859-1860) है, जहां किसानों ने नील की जबरन खेती के खिलाफ विद्रोह किया।

**Fixation of Land Revenue:** British policies aimed to fix the amount of revenue that had to be paid by landowners and tenants, sometimes regardless of the agricultural yield. For example, in the **Permanent Settlement of 1793** in Bengal, land revenue was fixed at a high rate and was expected to be paid in cash, leading to exploitation and frequent indebtedness of peasants.

**भूमि राजस्व का निर्धारण:** ब्रिटिशों ने भूमि राजस्व की एक निश्चित दर निर्धारित की, जिसे भूमि मालिकों और किसानों द्वारा चुकाना पड़ता था, चाहे कृषि उत्पादन कैसा भी हो। उदाहरण के लिए, 1793 में बंगाल में स्थायी समझौते के तहत भूमि राजस्व को उच्च दर पर निश्चित किया गया, जिसके कारण किसानों का शोषण और कर्ज में डूबना आम बात हो गई।

The **Ryotwari System**, implemented in places like Madras and Bombay Presidencies, fixed land revenue for each individual farmer (ryot), irrespective of the crop yield. This often led to farmers being unable to pay their fixed dues during bad harvests or droughts, which put them into debt or caused land dispossession.

**रियतवारी प्रणाली**, जो मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी में लागू की गई, ने प्रत्येक किसान (रियात) के लिए भूमि राजस्व निर्धारित किया, चाहे फसल की उपज कैसी भी हो। इसका परिणाम यह हुआ कि जब फसलें खराब होती थीं या सूखा पड़ता था, तो किसान अपनी निर्धारित राशि नहीं चुका पाते थे, जिससे उन्हें कर्ज या भूमि की नीलामी का सामना करना पड़ता था।

**Write a note on epidemics during the colonial period. What was the colonial government's response towards epidemics ?**

**औपनिवेशिक काल में महामारियों पर एक टिप्पणी। औपनिवेशिक सरकार की महामारी के प्रति प्रतिक्रिया क्या थी?**

### 1. Plague

One of the most significant epidemics was the **bubonic plague**, which began in the 1890s. It spread rapidly in urban areas like Bombay (now Mumbai) and Kolkata (Calcutta), and caused widespread panic and death. The government responded by implementing quarantine measures, including sealing off entire neighborhoods and imposing travel restrictions. While these measures were aimed at controlling the spread, they were harsh and led to resentment among the population.

### प्लेग

सबसे महत्वपूर्ण महामारियों में से एक **बुबोनिक प्लेग** था, जो 1890 के दशक में शुरू हुआ। यह तेजी से शहरी इलाकों जैसे मुंबई और कोलकाता में फैला, और बड़े पैमाने पर भय और मृत्यु का कारण बना। सरकार ने इसे नियंत्रित करने के लिए **क्वारेन्टाइन उपाय** लागू किए, जिनमें पूरे मोहल्लों को बंद कर देना और यात्रा प्रतिबंध लगाना शामिल था। हालांकि इन उपायों का उद्देश्य फैलाव को नियंत्रित करना था, लेकिन ये कठोर थे और जनसामान्य में असंतोष पैदा हुआ।

### 2. Cholera

Cholera was another recurrent epidemic during the colonial era. The British colonial government took steps to try and curb its spread, including measures like public health campaigns, the establishment of quarantine camps, and improvements in sanitation. However, these efforts were often inadequate, and cholera outbreaks continued to occur with alarming regularity.

### कालरा

कालरा औपनिवेशिक काल के दौरान एक और बार-बार फैलने वाली महामारी थी। ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने इसके फैलाव को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों, क्वारेन्टाइन शिविरों की स्थापना, और स्वच्छता में सुधार। हालांकि, ये प्रयास अक्सर अपर्याप्त थे, और कालरा के प्रकोप लगातार होते रहे।

### 3. Smallpox

Smallpox was also widespread during the colonial period. Vaccination campaigns were initiated by the British government, but these efforts were slow and poorly organized. The government focused on vaccinating soldiers and workers but did little for the general population, leading to continued outbreaks in rural and urban areas.

## चेचक

चेचक भी औपनिवेशिक काल में व्यापक था। ब्रिटिश सरकार ने टीकाकरण अभियानों की शुरुआत की, लेकिन ये प्रयास धीमे और अव्यवस्थित थे। सरकार ने सैनिकों और श्रमिकों को टीका लगाने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन सामान्य जनसंख्या के लिए बहुत कुछ नहीं किया, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में प्रकोप जारी रहे।

## Government's Response to Epidemics

The colonial government's response to epidemics was primarily focused on controlling the spread and maintaining public order, rather than prioritizing the health of the population. They often imposed strict quarantines, travel restrictions, and forced labor to contain the diseases. In many cases, the government did not provide adequate healthcare infrastructure and relied on traditional medicine. There was also a lack of research and understanding of the diseases, which delayed effective interventions.

## सरकार की महामारी के प्रति प्रतिक्रिया

औपनिवेशिक सरकार की महामारी के प्रति प्रतिक्रिया मुख्य रूप से फैलाव को नियंत्रित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने पर केंद्रित थी, न कि जनसंख्या के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने पर। उन्होंने अक्सर सख्त कारंटाइन, यात्रा प्रतिबंध और बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए मजबूर श्रम लगाया। कई मामलों में, सरकार ने पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान नहीं कीं और पारंपरिक चिकित्सा पर निर्भर रही। इसके अलावा, बीमारियों के बारे में शोध और समझ की कमी थी, जिससे प्रभावी उपायों में देरी हुई।

**The eighteenth century was a century of 'anarchy and chaos'. Examine.**

**अठारहवीं सदी को 'अराजकता और अव्यवस्था' का सदी कहा जाता है। इसका विश्लेषण करें।**

## 1. Decline of the Mughal Empire

The Mughal Empire, which had been the dominant power in India for over two centuries, started to weaken after the death of Aurangzeb in 1707. His successors were ineffective, and the empire faced internal rebellions, foreign invasions, and economic problems. This decline led to the fragmentation of the empire, with various provinces becoming autonomous and engaging in power struggles.

## मुगल साम्राज्य का पतन

मुगल साम्राज्य, जो दो शताब्दियों से भारत में प्रमुख शक्ति था, 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद कमजोर होने लगा। उनके उत्तराधिकारी प्रभावहीन थे, और साम्राज्य को आंतरिक विद्रोहों, विदेशी आक्रमणों और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस पतन के कारण साम्राज्य के विभिन्न प्रांत स्वतंत्र हो गए और सत्ता संघर्षों में उलझ गए।

## 2. Rise of Regional Powers

With the weakening of the Mughal central authority, regional powers such as the Marathas, Sikhs, Rajputs, and Nizams gained strength. While some of these powers, like the Marathas, attempted to create a pan-Indian empire, their rise often led to conflicts with one another. This fragmentation resulted in political instability and frequent battles for supremacy.

## क्षेत्रीय शक्तियों का उदय

मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के साथ, मराठा, सिख, राजपूत और निजाम जैसी क्षेत्रीय शक्तियाँ ताकतवर हो गईं। इनमें से कुछ शक्तियाँ, जैसे मराठा, एक अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनका उदय अक्सर आपस में संघर्षों का कारण बनता था। इस विखंडन के परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता और श्रेष्ठता की बार-बार लड़ाइयाँ होती थीं।

### 3. Invasions and Foreign Threats

The eighteenth century also witnessed several invasions, which contributed to the chaos. One of the most notable was **Nadir Shah's invasion in 1739**, which resulted in the plundering of Delhi and the weakening of Mughal authority. Later, the **Afghan invasion** under Ahmad Shah Durrani also disrupted the region. These invasions caused widespread destruction, depopulation, and economic distress.

## आक्रमण और विदेशी खतरे

अठारहवीं सदी में कई आक्रमणों ने भी अराजकता को बढ़ावा दिया। इनमें सबसे प्रमुख था **नदिर शाह का आक्रमण (1739)**, जिसके कारण दिल्ली में लूटपाट हुई और मुगल सत्ता कमजोर हो गई। बाद में, **अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण** भी क्षेत्र में गड़बड़ी का कारण बना। इन आक्रमणों ने व्यापक विध्वंस, जनसंख्या की कमी और आर्थिक संकट पैदा किया।

### 4. British Expansion and the Decline of Regional Powers

Amidst the chaos, the British East India Company began expanding its control over India. The Company took advantage of the internal conflicts between the regional powers and used them to its benefit. Key events like the **Battle of Plassey (1757)** and the **Battle of Buxar (1764)** marked significant victories for the British, allowing them to gain control over large parts of India. This led to the eventual consolidation of British power and the end of the political chaos.

## ब्रिटिश विस्तार और क्षेत्रीय शक्तियों का पतन

इस अराजकता के बीच, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ बढ़ानी शुरू की। कंपनी ने क्षेत्रीय शक्तियों के बीच आंतरिक संघर्षों का फायदा उठाया और इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। **प्लासी की लड़ाई (1757)** और **बक्सर की लड़ाई (1764)** जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं में ब्रिटिशों की बड़ी जीत ने उन्हें भारत के बड़े हिस्से पर नियंत्रण दिलाया। इससे अंततः ब्रिटिश सत्ता का समेकन हुआ और राजनीतिक अराजकता का अंत हुआ।

**What were the focal points of 1950-1980 industrial policy?**

## 1950-1980 की औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदु क्या थे?

### 1. Establishment of a Mixed Economy

The industrial policy focused on creating a mixed economy where both the private and public sectors played important roles. The public sector was given the responsibility of leading the development of heavy industries and infrastructure, while the private sector was encouraged to take part in consumer goods and less capital-intensive industries.

## मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना

औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना था, जहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का महत्वपूर्ण योगदान हो। सार्वजनिक क्षेत्र को भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे के विकास

की जिम्मेदारी दी गई, जबकि निजी क्षेत्र को उपभोक्ता वस्तुओं और कम पूंजी-गहन उद्योगों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

## 2. Role of Public Sector

The Indian government recognized that certain key industries, such as steel, power, heavy machinery, and defense, were crucial for the nation's development. Thus, these sectors were nationalized, and large-scale public sector enterprises were established. This aimed to reduce dependence on foreign countries and foster self-sufficiency.

## सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका

भारतीय सरकार ने यह पहचाना कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे इस्पात, ऊर्जा, भारी मशीनरी और रक्षा, राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार, इन क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया गया और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ स्थापित की गईं। इसका उद्देश्य विदेशों पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था।

## 3. Industrial Licensing System

To regulate and control the growth of industries, especially in the private sector, the government introduced an **industrial licensing system**. This system required businesses to obtain a license before starting new industrial ventures or expanding existing ones. It was intended to prevent excessive competition and promote balanced regional development.

## औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली

विशेष रूप से निजी क्षेत्र में उद्योगों के विकास को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए, सरकार ने **औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली** शुरू की। इस प्रणाली के तहत, व्यवसायों को नए औद्योगिक उपक्रम शुरू करने या मौजूदा उद्योगों का विस्तार करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक था। इसका उद्देश्य अत्यधिक प्रतिस्पर्धा को रोकना और क्षेत्रीय विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देना था।

## 4. Emphasis on Heavy and Basic Industries

The industrial policy of this period focused on the development of **heavy industries** and **basic industries** such as steel, coal, machinery, and power. These industries were seen as the backbone of economic growth and were critical for the country's industrialization. The government believed that without a strong base in heavy industries, the economy could not move forward.

## भारी और बुनियादी उद्योगों पर जोर

इस अवधि की औद्योगिक नीति का मुख्य ध्यान **भारी उद्योगों** और **बुनियादी उद्योगों** जैसे इस्पात, कोयला, मशीनरी, और ऊर्जा के विकास पर था। इन उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ के रूप में देखा गया था और ये देश के औद्योगिकीकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। सरकार का मानना था कि भारी उद्योगों में मजबूत आधार के बिना, अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती।

## 5. Import Substitution and Self-Sufficiency

The Indian government promoted the policy of **import substitution** to reduce dependence on foreign goods. The goal was to encourage domestic production of goods that were previously imported, thus conserving foreign exchange and boosting local industries.

## आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता

भारतीय सरकार ने **आयात प्रतिस्थापन** नीति को बढ़ावा दिया, ताकि विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को



कम किया जा सके। इसका उद्देश्य उन वस्तुओं का घरेलू उत्पादन बढ़ाना था, जिन्हें पहले आयात किया जाता था, जिससे विदेशी मुद्रा बचाई जा सके और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

**Examine the nature of women's employability in colonial India.**

**औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की रोजगार क्षमता की प्रकृति की जांच करें।**

### **1. Traditional Roles and Social Norms**

Women in colonial India were primarily confined to the domestic sphere, with their roles mostly being restricted to housework, child-rearing, and maintaining family honor. The deeply rooted social customs, particularly among the upper and middle classes, kept women from pursuing formal employment. The notion of women working outside the home was considered inappropriate and often looked down upon.

#### **पारंपरिक भूमिकाएँ और सामाजिक मान्यताएँ**

औपनिवेशिक भारत में महिलाएँ मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्र तक सीमित थीं, और उनकी भूमिकाएँ मुख्य रूप से घर के काम, बच्चों की परवरिश और परिवार की इज्जत बनाए रखने तक ही सीमित थीं। विशेष रूप से उच्च और मध्य वर्गों में गहरे निहित सामाजिक रिवाजों ने महिलाओं को औपचारिक रोजगार में भाग लेने से रोका। घर से बाहर काम करने वाली महिला की धारणा को अनुचित माना जाता था और अक्सर इसे नजरअंदाज किया जाता था।

### **2. Women's Employment in Colonial Industries**

Some women, especially from the lower socio-economic classes, found employment in the colonial industries. The **textile industry**, **tea plantations**, and **tobacco farms** employed a significant number of women in rural areas. However, these jobs were mostly unskilled, poorly paid, and involved exploitative working conditions. Women working in factories or plantations were subjected to harsh treatment and long hours of work.

#### **औपनिवेशिक उद्योगों में महिलाओं की नौकरियाँ**

कुछ महिलाएँ, विशेष रूप से निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्गों से, औपनिवेशिक उद्योगों में रोजगार प्राप्त करती थीं। **कपड़ा उद्योग**, **चाय बागान** और **तम्बाकू खेतों** में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की एक महत्वपूर्ण संख्या काम करती थी। हालांकि, ये नौकरियाँ ज्यादातर अप्रशिक्षित, कम वेतन वाली और शोषणकारी कार्य स्थितियों में होती थीं। कारखानों या बागानों में काम करने वाली महिलाओं को कठोर व्यवहार और लंबी कार्यघंटियों का सामना करना पड़ता था।

### **3. Women in the Public Sector**

As the British colonial administration began to establish schools and hospitals, women were gradually employed in teaching, nursing, and other public services. **Missionary schools** and **Christian institutions** were among the first to employ women as teachers and nurses. This was a significant shift as women began to enter occupations that were considered respectable

in the colonial context. However, such opportunities were mostly restricted to the educated upper classes.

### सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएँ

जैसे-जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना की, महिलाओं को धीरे-धीरे शिक्षण, नर्सिंग और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में काम पर रखा जाने लगा। **मिशनरी स्कूलों** और **ईसाई संस्थाओं** में महिलाओं को शिक्षिकाओं और नर्सों के रूप में नौकरी दी गई। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था क्योंकि महिलाएँ औपनिवेशिक संदर्भ में सम्मानजनक मानी जाने वाली नौकरियों में प्रवेश करने लगीं। हालांकि, ऐसी अवसरें ज्यादातर शिक्षित उच्च वर्गों तक ही सीमित थीं।

## SHORT NOTE

### Bank Nationalisation बैंक राष्ट्रीयकरण:

**Bank Nationalisation** refers to the process when the government takes control of privately owned banks. In India, this happened in two major phases.

**बैंक राष्ट्रीयकरण** उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब सरकार निजी स्वामित्व वाले बैंकों को अपने नियंत्रण में ले लेती है। भारत में यह दो प्रमुख चरणों में हुआ।

**1969 Bank Nationalisation:** On July 19, 1969, the Indian government took control of 14 major private sector banks, making them public sector banks. This move aimed to ensure that banking services were available to all people, especially in rural areas, and to align the banking system with national development goals.

**1969 बैंक राष्ट्रीयकरण:** 19 जुलाई 1969 को भारतीय सरकार ने 14 प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों को अपने नियंत्रण में लिया, जिससे वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बन गए। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी लोगों, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध हों और बैंकिंग प्रणाली को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ना था।

**1980 Bank Nationalisation:** In 1980, the government nationalized 6 more private banks to increase the reach of banking services and make the sector more efficient in supporting economic growth.

**1980 बैंक राष्ट्रीयकरण:** 1980 में, सरकार ने 6 और निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया ताकि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जा सके और इस क्षेत्र को आर्थिक विकास का समर्थन करने में अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

The goal of nationalizing the banks was to promote financial inclusion, provide credit to key sectors like agriculture and industry, and reduce the concentration of wealth in a few private hands. It was a step to make banking serve the public interest rather than private profits.

बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना और कुछ निजी हाथों में संपत्ति के केंद्रीकरण को कम करना था। यह एक कदम था जिससे बैंकिंग का उद्देश्य निजी लाभ के बजाय सार्वजनिक हित की सेवा करना था।



## Birla Brothers

Birla Brothers is a well-known business group in India, which is part of the Aditya Birla Group. The Birla Group was founded by Seth Shiv Narayan Birla in the early 1900s. Over the years, it grew from a small trading business to a huge company involved in many industries like textiles, cement, metals, chemicals, and financial services. The Birla family has also made big contributions to social causes, especially in education, healthcare, and rural development.

The Birla group is famous for its strong business skills and ethical practices. Today, it is a respected name in India and around the world. It has helped shape India's industrial growth and is now one of the largest companies in the world, operating in many countries.

**बिरला ब्रदर्स** भारत का एक प्रसिद्ध व्यापारिक समूह है, जो आदित्य बिरला समूह का हिस्सा है। बिरला समूह की स्थापना सेठ शिव नारायण बिरला ने 1900 के दशक की शुरुआत में की थी। सालों के दौरान, यह एक छोटे व्यापार से बढ़कर एक विशाल कंपनी बन गई, जो वस्त्र, सीमेंट, धातु, रसायन और वित्तीय सेवाओं जैसे कई उद्योगों में काम कर रही है। बिरला परिवार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे सामाजिक कार्यों में भी बड़ा योगदान दिया है।

बिरला समूह अपनी मजबूत व्यापारिक समझ और नैतिक तरीके से काम करने के लिए जाना जाता है। आज, यह भारत और दुनिया भर में सम्मानित नाम है। इस समूह ने भारत के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाई है और अब यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन चुका है, जो कई देशों में काम कर रहा है।

## Globalization

Globalization means the process of countries and people becoming more connected to each other. This happens because of better communication, trade, and technology. Through globalization, people, goods, services, and ideas travel more easily across countries. This has helped businesses grow, economies become stronger, and people learn about different cultures.

However, globalization also has some challenges. While it brings economic growth, it can also cause problems like inequality between rich and poor and harm to the environment. Some people feel that globalization makes it harder for local businesses to compete with big international companies.

**वैश्वीकरण** का मतलब है देशों और लोगों का एक-दूसरे से अधिक जुड़ना। यह बेहतर संचार, व्यापार और तकनीक की वजह से होता है। वैश्वीकरण के माध्यम से लोग, वस्त्र, सेवाएँ और विचार अधिक आसानी से देशों में आते-जाते हैं। इससे व्यापारों को बढ़ने, अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत होने और लोगों को अलग-अलग संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद मिली है।

हालांकि, वैश्वीकरण के कुछ चुनौतीपूर्ण पहलू भी हैं। जबकि यह आर्थिक वृद्धि लाता है, यह अमीर और गरीब के बीच असमानता और पर्यावरण को नुकसान जैसी समस्याएँ भी पैदा कर सकता है। कुछ लोग महसूस करते हैं कि वैश्वीकरण के कारण स्थानीय व्यापारों के लिए बड़े अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला करना कठिन हो जाता है।

Scholarly Minds